







# पशुपालन में चारे का संकट

आजादी के बाद से ही वन, स्थायी चरागाह, परती भूमि, घास के मैदान लगातार सिकुड़ गए हैं। इसी का नतीजा है कि जहाँ 1947 में देश में सात करोड़ हेक्टेयर में घास क्षेत्र थे वहाँ अब यह आंकड़ा घट कर 3.8 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। यही कारण है कि आज देश में पशुचारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हरे और सूखे चारे के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़ा भी नहीं है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक भारत 35.6 फीसद हरे चारे और 10.9 फीसद सूखे चारे की कमी झोल रहा है। कुदरती आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि की दशा में यह संकट विकराल रूप धारण कर लेता है। पशु चारे के अलावा दुधारू पशुओं के लिए मोटे अनाज, खली और अन्य पौष्टिक तत्त्वों की भारी कमी है। पौष्टिक पशु चारे में काम आने वाले मोटे अनाज दूध के भाव मिल रहे हैं, जिसका सीधा नतीजा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट के रूप में सामने आ रहा है। एक बड़ी समस्या यह है कि पशु चारे में हरी घास और हरे



संचालित ही नहीं की जा सकती है जैसे हिमाचल प्रदेश। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य। यहां दुधार पशुओं के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए पशुपालन होता है। संसद में प्रस्तुत कृषि संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी पशु चार की कमी पर गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चरागाहों की जगहों को खेतों में तब्दील कर उन पर खायान्न, तिलहन और दालें उगाई जा सकती हैं। इसीलिए चारे वाली फसलों की खेती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हांनी नहीं, फसलों के अन्य उत्पादों के विविध उपयोग के कारण भी चारे की मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय पशुओं की कम उत्पादकता के लिए चारा और पशु आहार की कमी जिम्मेदार है। देश में जितना ध्यान पशुओं के नस्ल सुधार पर दिया जाता है उसका दसवाहिस्सा भी पशुओं की पोषण क्षमता बढ़ाने पर नहीं दिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि नस्ल सुधार और प्रभावी पशुधन जैसे लक्ष्य तब तक हासिल नहीं होंगे। जब तक कि मवेशियों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था न की जाए।

इसी को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने एक भारतीय चारा नियम की स्थापना करने, तिलहन खाली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और डंठल बर्बाद करने वाली कंबाइंड हावर्स्टर मशीन से गेहूं आदि की कटाई पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। यह भी मांग की जा सकती है कि केंद्र सरकार पशुपालन, डेयरी उद्योग और मर्स्यपालन को कृषि क्षेत्र के बराबर तवज्ज्ञों दे और इनमें संलग्न लोगों को कम व्याज दर पर ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं दी जाएं। गौरतलब है कि सोया खाली के बढ़ते निर्यात से घरेलू बाजार में उसकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं और वह अधिकतर पशुपालकों को पूर्वुच से दूर होती जा सकती है।

चूंगी गुणवत्ता का चारा न सिर्फ दूध उत्पादन के लिए बल्कि डेयरी व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए भी जरूरी है। सकल घरेलू उत्पाद में अकेले भैंस का

योगदान गेहूँ-धान के समिलित योगदान इससे पशुधन और पशु चारे के महाविद्युत आसानी से लगाया जा सकता है। ग्राम का अहम अंग होने के साथ-साथ संतुलन और स्वाध्य तथा पोषण सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद का उत्पादन सरकारों की वरीयता सूची में विफल रहा है। देखा जाए तो पशु चारे की किल्लत अदूरदर्शी नीतियां जिम्मेदार हैं। गौरव मांस और दूसरे पशु उत्पादों की कुल सत्र फीसद हिस्सा मवेशियों के चारे से है। इसके बावजूद अभी तक न उपलब्धता बढ़ाने और न ही इनकी तरफ की ओर समुचित ध्यान दिया गया है। प्राकृतिक चरागाहों के कम होने का लगाने और सार्वजनिक चरागाह में रखने या उनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए कोई नीति नहीं है। फसल चक्र में शामिल कर चारा फसलों के उत्पादन की योजना अब तक उपेक्षित रही है। ट्रैक्टर भूमि में से पांच फीसद से भी कम पर जाती है। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि लिए आबादित बजट का मामूली हिस्सा आहार क्षेत्र के विकास के लिए खच्चा चारा फसलों के उन्नत बीजों के विकास सरकारी और न ही निजी क्षेत्र की सरकारी सरकार की उदासीनता को बजटीय उपलब्धता द्वारा उत्पादन का उन्नत बीजों के विकास को लिए बहुत 141 प्रावधान किया गया था, जिसका सारा करोड़ रुपए था। इसे ऊंट के मुंह जाएगा। लंबे अरसे से उपेक्षित पशु जनरेंट्र मोदी सरकार ने ध्यान दिया है।

## सम्पादकाय



सङ्केत के और रेल पटरियां किसी भी देश की विकास रेखा मानी जाती हैं। यही आधारभूत ढांचे का सबसे मजबूत पक्ष होती है। इसलिए हर देश दुतगमी मार्गों और रेल पटरियों के विकास तथा विस्तार पर विशेष ध्यान देता है। जम्मू-कश्मीर की चिनाब नदी पर बने मेहराबदार पुल को इसी अर्थ में देखा जा सकता है। जम्मू-कश्मीर अभी तक देश के रेल संजाल से कटा हुआ था। इस पुल के चालू हो जाने के बाद वह भी देश की मुख्यधारा रेल यातायात से जुड़ गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, एफिल टावर से भी ऊंचा। इसे बनाना निस्संदेह बड़ी चुनौती थी। जिस इलाके में इसे बनाया गया है, वह भूकम्प की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहां हर समय भूकम्प का खतरा बना रहता है। फिर, ऊंचाई अधिक होने के कारण इस पर पड़ने वाले वायुदाब और मौसम के प्रकाप से बचाव के उपाय करना भी कठिन था। मगर काबिल अभियंताओं ने इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया और एक भिसाल के रूप में इसे खड़ा कर दिया। इसे बनाने में लंबा समय लग गया। इस दैरान कई तरह की अड़चनों का भी सामना करना पड़ा। मगर अब इसके बन कर तैयार हो जाने से अनेक कठिनाइयां दूर हो जाने की उम्मीद जगी है। हालांकि कश्मीर और लद्दाख सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में नई सुरंगें बन जाने से सड़कों पर वाहनों की गति भी बढ़ गई है, मगर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के जरिए आवागमन उस तरह कभी आसान और सुविधाजनक नहीं रहता, जिस तरह रेल पटरियों से होता है। रेल मार्ग के जरिए न केवल मुसाफिरों की आवाजाही सुगम हो जाती है, बल्कि माल दुलाई में बहुत आसानी होती है। रेल मार्गों का विकास औद्योगिक उन्नति के लिहाज से बहुत जरूरी माना जाता है। इस अर्थ में चिनाब पुल के खुल जाने से कश्मीर में औद्योगिक विकास और रोजी-रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं खुल गई हैं। वहां के हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद अब आसानी से देश के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। जो कश्मीरी युवा और बहुत सारे स्थानीय लोग आमतौर पर पर्यटन पर निर्भर थे और वर्ष के कुछ महीनों में ही कारोबार कर पाते थे, उन्हें अब पूरे साल कारोबार का अवसर मिल सकेगा। स्वाभाविक ही, इस तरह वहां बेरोजगारी कम होगी और जो युवा आतंकी संगठनों के बरगलाने से गुमराह हो जाया करते थे, उन्हें तरक्की का रास्ता नजर आएगा। चिनाब पुल शुरू हो जाने के बाद इस पर तेज रफ्तार गाड़ियों की आवाजाही बढ़ेगी, तो वहां सैलानियों का पहुंचना भी तेज होगा। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि कश्मीर को किसी तरह भारत के दूसरे हिस्सों से अलग-थलग रखा जाए। इस तरह चिनाब पुल एक तरह से उसकी कोशिशों पर पानी फेरने में मददगार होगा। दूसरी बात कि यह पुल बन जाने से कश्मीर घाटी और लद्दाख तक सैन्य साजों-सामान और सैनिकों की पहुंच तेज हो जाएगी। अभी रोज ही लगभग पूरा दिन लगा कर सैन्य टुकड़ियां श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर पहुंचती हैं। प्रधानमंत्री ने पुल के साथ-साथ तेज रफ्तार वंदेभारत गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई। यानी अब बहुत कम समय में श्रीनगर तक पहुंचना संभव हो गया है।

## वन्यजीवों का संरक्षण



पिछले कुछ वर्षों से वन्य जीव-जंतुओं पर नजर दौड़ाई जाए तो धीरे-धीरे उनकी संख्या में गिरावट आनी शुरू हो रही है। इसका प्रमुख कारण है कि हम वन्य जीव-जंतुओं को बचाने में धीरे-धीरे नाकाम सफिल हो रहे हैं। किसी राज्य में हाथी पाए जाते हैं तो किसी राज्य में शेर और बाघ चीता आदि दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय से आ रही प्राकृतिक आपदाएं भी इनकी जान ले रही हैं। यो सरकार ने संरक्षित जीव-जंतुओं का शिकार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिवर्द्ध लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी चोरों-छिपे इनका शिकार किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि कहीं बिजली के करंट के कारण यह जीव-जंतु मौत का शिकार होते हैं तो कहीं जंगलों में लगने वाली आग इनको अपनी चपेट में ले लेती है। यहां तक कि अनेक बार विभिन्न राज्यों में चोरों-छिपे इनका शिकार भी किया जाता है। जहां से रेलगाड़ी गुजरती है, वहां पर भी बड़ी संख्या में विभिन्न तरह के जीव-जंतु हादसे का शिकार होते हैं। हमें खासतौर पर संरक्षित जीव-जंतुओं को बचाना होगा और उसके साथ-साथ उनके प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होने से बचाने की रूप जंतु बीमा सम घट मुंह विस प्रवृ ही जी दृष्टि भार एक का देश सह उस मह युक्र दिय

कोशिश करनी होगी। इस बात पर भी विशेष से ध्यान देना होगा कि इस तरह के जीव-ओं में समय-समय पर विभिन्न तरह की आरियां भी आती रहती हैं और उनके इलाज की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा, कुछ य पहले केरल में एक हायिनी के साथ जैसी नाहुँ थी, उसने दिल ढहला दिया था। उसके में पटाखों का अनार डाल दिया गया, जिसमें फ्रोट से उसका मुँह फट गया। इस प्रकार की तरियों के खिलाफ सख्ती बरतनी होगी। साथ मन्मुद में रहने वाले, लेकिन लुप्त होते जा रहे अंजतुओं को प्राकृतिक और इस तरह के त हो रहे वातावरण से बचाना होगा। आज त विश्व में चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान तटस्थ देश की भूमिका निभा रहा है। भारत अपना एक रिकार्ड रहा है। वह किसी भी बड़े की छोटे के लिए किसी भी तरह की ज्यादती न नहीं करता। फिर चाहे ज्यादती करने वाला का अपना दोस्त ही क्यों न हो। आज रूस एक अशक्ति है। उसने अपने से छोटे पड़ोसी देश न पर हमला करके उसे तहस-नहस कर दिया है। विश्व एवं भारत की नजर में भी यह एक ज्यादती है। उसके इस व्यवहार को भारत कर्तव्य सही नहीं मानता। हालांकि इसके लिए वह रूस का विरोध भी नहीं करता, मगर रूस के इस कृत्य का समर्थन भी नहीं करता। खुद रूस भी भारत को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वह भारत से इस बात के लिए नाराजगी जाहिर नहीं करता और भारत-रूस के संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसका दोनों देशों के आयात-निर्यात पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। भारत का रूस से कई वस्तुओं के लेनदेन का बरसों से व्यापार चला रहा है। इसलिए आज इसी कारण भारत की मांग पर रूस उसे सस्ता कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। फिर रूस कच्चा तेल जी-7 की मूल्य सीमा के खिलाफ जाकर भारत को पर्याप्त धूप पर भी तेल दे रहा है। यो भारत को तेल आपूर्ति करने वाला एक देश इकाक भी है। यह देश भी हमें काफी सस्ता तेल निर्यात करता रहता है। देखा जाए तो हमारा तेल आपूर्ति देश सजुरी अरब भी है जो हमें 20.8 फीसद तेल निर्यात करता है। इसके बाद इकाक हमें 20.6 फीसद तथा इसी तरह से रूस है जो आज हमें 18.2 फीसद तेल निर्यात कर रहा है।

उम्र से पहले

जिन समस्याओं को सुलझाने की क्षमता मुझमें है, वे तुरंत नजर आ जाती हैं, पर ज्यादातर दिखने के बावजूद दिखाई नहीं देती। शुरुआत में कोफ्त होती थी तो कुछ न कुछ बकबक कर यानी बेमानी बोल कर काम चला लेता था, लेकिन रोज एक ही तरह का काम व्यक्ति को उबाऊ बना देता है, जैसे मैं होने लगा हूं। हालांकि हाल की एक घटना बहुत से सवालों को लिए हुए है, जिनमें इतना ताजापन और तीखापन है कि फिर से कुछ दिन सीखने और सोचते रहने का मसाला हाथ लग गया है।

और सच्चा नागरिक बनाने की इतनी जल्दी है कि अभी ठीक से बोल भी पाने वाले बच्चों का दाखिला उसकी उम्र से ज्यादा बड़ी कक्षाओं में करा दिया गया है। जो बच्चे अभी आंगनबाड़ी जाने योग्य भी नहीं हैं, उनका नामांकन स्कूल की उन कक्षाओं में कर दिया गया, जिनमें उन्हें पहुंचने में अभी समय लगता। स्कूल की एक शिक्षिका ने कारण बताया कि पुराने शिक्षक साधियों ने स्कूल में घटते नामांकन को बढ़ाने के लिए गांव के उन बच्चों का दाखिला स्कूल में कर दिया जो अभी गोद में ही थे और उनके नाम का मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन उठाया जाने लगा। जब तक उन्होंने चलना शुरू किया और स्कूल में दाखिले के लिए आए तो उन्हें उन कक्षाओं में बैठाया जाने लगा, जिनमें उनका छोटी उम्र में ही दाखिला कर दिया गया था। चूंकि कागज यानी दस्तावेज ही सब कुछ बोलत हैं, इसलिए हमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता कहां कि कोई इस बात की जांच भी करे। सवाल है कि इन सबके पीछे का कारण क्या है। जानने की कौशिश की तो पता चला कि इसके पीछे शिक्षा का अधिकार कानून है, जिसके मुताबिक तीस विद्यार्थियों पर एक शिक्षक और तीस से अधिक पर दो शिक्षक प्रति स्कूल नियुक्त किए जाने हैं। अगर स्कूल में बच्चों का नामांकन कम होता है तो उसके अनुसार शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। माटे तौर पर तीस से साठ के बीच विद्यार्थियों की संख्या रही तो दो शिक्षक स्कूल में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे ज्यादा हुई तो तीन शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन स्कूल से बच्चों की संख्या कम होने लगी तो शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए उन बच्चों को भी उम्र से बहुत पहले स्कूल में दाखिला दे दिया गया, जो अभी गोद में ही थे। ऐसे स्कूल में बच्चे क्या सीख रहे होंगे? कक्षा एक से पांच तक के बच्चों में किस तरह का अंतर होगा? क्या ऐसी स्थिति में हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। कहा जाता है कि स्कूल का काम बच्चों को केवल लिखान-पढ़ना सिखाना नहीं, बल्कि मूल्यों के साथ-साथ उसका सर्वांगीण विकास करना भी है। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसे ही किया जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास? यह समस्या वास्तव में परेशान करने वाली है।











